**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3929**

**सोमवार, 2 अप्रैल,2018/11 चैत्र, 1940 (शक)**

**गैर-सरकारी परिवहन समूहक कम्पनियों द्वारा ज्यादा किराया वसूलना**

**3929. श्री हिशे लाचुंगपाः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी परिवहन समूहक कम्पनियों के ‘सर्ज’ किराया निर्धारण की परिपाटी को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके परिणामस्वरूप ये प्रचालक इस देश की जनता से काफी ज्यादा किराया वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (ग):** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सड़क द्वारा परिवहन राज्‍य का विषय है। सर्ज मूल्‍य-निर्धारण के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव केन्‍द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्‍न परमिटों की जांच करने एवं एक मसौदा स्‍कीम निरुपित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए टैक्‍सी नीति से संबंधित दिशा- निर्देश प्रस्‍तावित करते हुए दिसंबर, 2016 माह में रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। इस रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्‍वीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट की प्रति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट ([www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in)) पर उपलब्‍ध है। इसे राज्‍यों के साथ सांझा किया गया है।

\*\*\*\*\*